कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री केदार नाथ सिंह) : (क) से (ग). मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा 1969 में तैयार की गई बारगी परियोजना में नर्मदा बेसिन में राज्य के जबलपुर और नरसिंह पुर जिलों के 3.33 लाख हेक्टेयर की सिंचाई परिकल्पित है। राज्य सरकार से बारगी जल की बेसिन से बाहर रीवा जिले में समुपयोजन करने के संबंध में कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। बारगी परियोजना की अद्यतन अनुमानित लागत 124.15 करोड़ रुपये है।

चूंकि बारगी परियोजना नर्मदा बेसिन में पड़ती है और नर्मदा के जल से संबंधित विवाद अभी नर्मदा जल विवाद न्यायाधिकरण के पास न्यायनिर्णयन के लिए है, अतः न्यायाधिकरण का निर्णय उपलब्ध हो जाने के उपरान्त ही बारगी परियोजना के आकार को अन्तिम रूप दिया जा सकता है।

Committee on Forestry

3113. SHRI VAYALAR RAVI: Will the Minister of AGRICULTURE AND IRRIGATION be pleased to state:

(a) whether Government appointed a Committee to study Forestry in India and whether the Committee submitted a report; and

(b) if so, salient features of the report and the steps taken to implement it?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE AND IRRIGATION (SHRI PRABHUDAS PATEL): (a) No, Sir. The Government of India have not set up a Committee to study in India. However, the Central Board of Forestry had constituted a Sub-Committee of Selected States' Forest Ministers and technical experts for revision of the National Forest Policy. This report is not finalised.

(b) Question does not arise.

चौथी और पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राजस्थान और मध्य प्रदेश में लघु सिंचाई योजनाएं

3114. **श्री गंगा चरण दीक्षित** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश और राजस्थान के लिये चौथी योजना की अवधि में लघु सिंचाई परियोजनाओं के लिए कितनी राशि की मंजूरी दी गई ; और

(ख) पांचवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि में इन राज्यों के लिए कितनी नई लघु सिंचाई परियोजनाओं की मंजूरी दी गई है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज़ खां) : (क) चौथे पंचवर्षीय योजना की अवधि के दौरान लघु सिंचाई योजनाओं के लिये राज्य सरकारों द्वारा राज्य योजना के अंतर्गत धनराशि प्रदान की गई थी और केन्द्रीय सहायता समग्र योजना के लिये एक मुश्त ऋण और अनुदान के रूप में स्वीकृति की गई थी। केन्द्रीय सहायता का सम्बन्ध विकास योजना के किसी शीर्ष से नहीं था। चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि के दौरान मध्य प्रदेश और राजस्थान में लघु सिंचाई के अंतर्गत किया गया योजना क्षेत्र का कुल वित्तीय परिव्यय क्रमशः 43.83 करोड़ रुपये और 12.35 करोड़ रुपये था।

(ख) लघु सिंचाई योजनाएं विभिन्न प्रकार की हैं, जिनमें खोदे गए कुएं, नलकूप, पम्पसेट, सतही जल का भंडारण, पथान्तरी एवं उठाऊ सिंचाई परियोजनाएं, आदि शामिल हैं। ये कार्य संख्या में अधिक होने के कारण इनका नियोजन संख्या के आधार पर नहीं किया जाता है, बल्कि वित्तीय परिव्यय एवं क्षेत्र के लाभों के आधार पर किया जाता है। मध्य प्रदेश तथा राजस्थान में पांचवीं पंचवर्षीय योजना के प्रारूप में राज्य योजना

का वित्तीय परिव्यय एवं वास्तविक लाभ नीचे दिये गये हैं :—

राज्य	योजना क्षेत्र का परिव्यय (करोड़ रुपयों में)	वास्तविक लक्ष्य (लाख हैक्टार)
मध्य प्रदेश	52.00	6.00
राजस्थान	12.89	1.32

Model High Schools

3115. PROF. NARAIN CHAND PARASHAR: Will the Minister of EDUCATION, SOCIAL WELFARE AND CULTURE be pleased to state:

(a) whether Government have decided to set up Model High Schools at each of the C.D. Blocks of the country;

(b) if so, whether any such Model Schools has since been set up so as to provide a model for the rural areas as has been done by establishing central schools, in the urban areas; and

(c) names of the schools established so far, State-wise?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF EDUCATION AND SOCIAL WELFARE AND IN THE DEPARTMENT OF CULTURE (SHRI D. P. YADAV): (a) to (c). The proposal to establish model comprehensive secondary schools at the district level is still under consideration.

Provident Fund Accounts of the Workcharged Staff of C.P.W.D.

3116. SHRI BHOLA MANJHI: Will the Minister of WORKS AND HOUSING be pleased to state:

(a) whether the Provident Fund accounts of the workcharged staff of all Divisions of C.P.W.D. for the year ending 31st March, 1975 have been supplied to the subscribers; and

(b) if so, when and if not, reasons therefor?

THE MINISTER OF WORKS AND HOUSING AND PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI K. RAGHU RAMAIAH): (a) and (b). There are three Zonal Offices in the C.P.W.D. at Delhi, Bombay and Calcutta which maintain the Provident Fund Accounts of the Workcharged Staff.

Provident Fund Account statements of all the Divisions covered by the Zonal Offices located at Bombay and Calcutta for the period ending 31st March, 1975 have been supplied. In the Zones located at Delhi, out of 90 Divisions involved in the matter, the statements for 22 Divisions have already been supplied. Action to supply Statements of the workcharged Staff of the remaining Divisions is in progress.

The reason for delay in supplying the statements to the Workcharged Staff of the remaining Divisions of the Delhi Zone is that, maintenance of Provident Fund Accounts of this category of Staff has been switched over to the new accounting system on Bradma Machines. Consequently, the statements of Provident Fund Accounts for the year ending 31st March, 1975, which are being issued for the first time under this new accounting arrangement, have involved additional work of allotment of new account numbers, the necessary information in respect of which had to be obtained from the Divisions concerned.

Payment of Compensation to Workers Retrenched from Arunachal Pradesh Circles of C.P.W.D.

3117. SHRI C. JANARDHANAN: Will the Minister of WORKS AND HOUSING be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 2199 on the 12th August, 1974 re-